

I/177136/2023

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेशऑडिट भवन, टी सी-35-V-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010

स.म.ले.(ले.प.-II)/ प्रशा./P-3/अचल सम्प./अराजपत्रित/ 173

दिनांक 23/01/2023

कार्यालय आदेश

अचल/चल संपत्ति के क्रय के संबंध में प्रशासन अनुभाग के संज्ञान में आया है कि कार्यालय के कई अधिकारी/कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उपनियम 18 (2) एवं 18 (3) का उल्लंघन कर रहे हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है और भविष्य में कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को इसकी पुनरावृत्ति न करने हेतु निर्देशित किया जाता है। कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के उपनियम 18 (2) एवं 18 (3) को नीचे पुनः उद्धृत किया जाता है-

In connection with the purchase of immovable/movable property, it has come to the notice of the Administration Section that several officers/employees of this office are violating sub-rules 18 (2) and 18 (3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. This has been taken seriously by the competent authority and all the officers/employees of this office are directed not to repeat the violation of the above rules in future. The above sub-rules 18 (2) and 18 (3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 is hereby reproduced below for ensuring strict compliance for, by all the officers/employees working in the office -

*'The undersigned is directed to say that in accordance with the provisions of sub-rule (2) of the Rule 18 of the CCS (Conduct) Rules, 1964, all Government servants coming within the purview of these Rules are required to make a report to the prescribed authority before entering into any transaction of immovable property in their own name or in the name of a member of family. If the transaction is with a person having any official dealings with the Government servant, the Govt. servant is required to obtain prior sanction of the prescribed authority. Sub-rule (3), ibid provides that all Govt. servants should give an intimation to the prescribed authority within one month of entering into any transaction off movable property, the value of which exceeds the monetary limits prescribed in that Rule. In case any such transaction is with a person having official dealing with the Government servant, prior sanction of the prescribed authority is necessary.'*

भविष्य में उक्त नियम का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

In future, in case of violation of the above Rules, disciplinary action will be taken as per the rule.

हस्ता/-

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

स.म.ले.(ले.प.-II)/ प्रशा./P-3/अचल सम्प./अराजपत्रित/ 2713

दिनांक 23/01/2023

Handwritten notes and signatures:

- 23/1/23
- Noted.
- Circular file upload
- 23.1.22

I/177136/2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरि. उपमहालेखाकार/ ए.एम.जी.-III एवं प्रशासन
2. उपमहालेखाकार / ए.एम.जी. - II & ए.एम.जी.-IV
3. सचिव, महालेखाकार, (ले.प.-II), लखनऊ, उ.प्र.
4. समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य प्रशासन/IT सेल/पी.सी./ए.एम.जी.- IV (प्रो.)/  
ए.एम.जी.-III(प्रो.) /ए.एम.जी.-III(प्रो.)/रिपोर्ट-1/रिपोर्ट-II/रिपोर्ट-III/ITA
5. स.ले.प.अ./ IT सेल, इस आशय के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश की प्रति, कार्यालय के  
आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का कह करें।
6. सूचना पट्ट- प्रथम एवं द्वितीय तल

Signed by Sunil Kumar  
Pandey

Date: 20-01-2023 17:45:00

Reason: Approved

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन